

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)  
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र  
केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ई-5, लिंक रोड नं. 3  
रविशंकर नगर भोपाल-462016

विषय:- जिला बैतूल के अंतर्गत प्रभुढाना जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 7.002 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPC 014/2019-BHO/190 दिनांक 28.02.2019


—0—

विषयांतर्गत मे भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से प्रकरण मे 05 बिन्दुओं की चाही गयी जानकारी प्राप्त कर निम्नानुसार संलग्न प्रेषित है :-

1. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक D(i) में सर्वे आफ इंडिया की 1:50,000 स्केल की टोपोशीट पर alternative- I & alternative- III चिन्हित कर वेबपोर्टल पर अपलोड कर दिये गये है, एवं मानचित्र की हार्डकापी संलग्न है।
2. ग्राम चौकी एवं रातामाटी के अंतर्गत लगभग 1400 हेक्टेयर वनभूमि आती है। इस 1400 हेक्टेयर वन क्षेत्र का उपयोग ग्रामीणों द्वारा मवेशियों को चारा ओर ईंधन के उपयोग हेतु किया जाता है। इस परियोजना में लगभग 7 हेक्टेयर वन क्षेत्र का उपयोग होने के बाद भी ग्रामीणों के पास पर्याप्त रकबे में उक्त कार्य के लिये वन क्षेत्र उपलब्ध रहेगा।
3. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक C(ii) की टेबल मे प्रस्तावित वनभूमि 7.002 हे0 की संशोधित KML file अपलोड कर दी गयी है एवं सॉफ्टकापी मे संलग्न है।
4. इस बिन्दु मे वनमण्डलाधिकारी, (सा0) दक्षिण वनमंडल बैतूल ने बताया है, कि Dam axis ओर Spill way का कुछ हिस्सा संरक्षित वनभूमि एव कुछ हिस्सा निजी भूमि के अन्तर्गत आता है। इसलिए Dam axis ओर Spill way को KML file मे दिखाया नही गया है।
5. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक K(i)(a) में FRA प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है, तथा हार्डकापी मे संलग्न है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

  
(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-3/16/2018/10-11/2/1818  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 21-5-18

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) बैतूल वृत्त बैतूल, मध्यप्रदेश।
  2. वनमण्डलाधिकारी, (सा0) दक्षिण वनमंडल बैतूल, मध्यप्रदेश।
  3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, बैतूल, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

4/5/18  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल



**FORM-II**  
(For projects other than linear projects)  
Government of Madhya Pradesh  
Office of the District Collector, Betul.



No.-FRA/2018/13/4767

Dated 25-06-2018


**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that 7.002 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of *E.E. Water Resources Divi.No.2 Betul (For Minor Tank Probhudhana)*. (name of user agency) for Dam district falls within jurisdiction of *Villages Chouki, Betul Tahsil & Prabhudhan (Ratamati) Village in Bhainsdehi Tahsil.* village(s) in *Bhainsdehi.* tehsils.

It is further certified that :

- a- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 7.002 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting's of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Forest Rights Committee(s) Betul and the District Level Committee are enclosed as annexure A to B annexure -----
- b- the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- c- the each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of *Chouki/Prabhudhana (Ratamati).* villages(s) is enclosed as annexure A to annexure B.
- d- the discussion and decisions on such proposals has taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- e- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- f- the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl.: As above.

  
 (Full name and official seal of the District Collector)  
**SHASHANK MISRA**  
**COLLECTOR**  
**2 DISTT.-BETUL**